>

Title: Need to restore PDS quota of foodgrains and edible oil for Uttarakhand.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदया, उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा 18,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का कोटा आवंटित था, जो धीरे-धीरे घटते-घटते 6,000 मीट्रिक टन रह गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा इस बारे में लगातार मांग की गयी है और मैंने भी इस मामले को कई बार सदन में उठाया है, लेकिन यह कोटा बढ़ा नहीं है। इसकी वजह से बीपीएल कैटेगरी के परिवारों को भी अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसी तरह से खाद्य तेल, जो 15 रूपए किलो प्रति परिवार अन्त्योदय और अन्नपूर्ण योजना में मिलना था, उसकी सुविधा भी उत्तराखण्ड राज्य को नहीं मिली है। साथ ही चीनी, मिट्टी का तेल और रसोई गैस के जो कनेक्शन्स मिलने हैं, उनमें वृद्धि नहीं होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपके माध्यम से मेरी मांग है कि हमारा खाद्यान्न का कोटा बहाल किया जाए, खाद्य तेल 15 रूपए किलो प्रति परिवार की जो योजना है, उसका लाभ दिया जाए और रसोई गैस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।